

प्रभु,

दिनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुनाग-01.

देहरादून दिनांक ०५ फरवरी, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति शिल्पी ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।


महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-277/XXVII(1)-01/2006-12(बजट)/2004, दिनांक 18 फरवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति शिल्पी ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 52,00,000/- (रुपये बावन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वातन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुगम्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. उक्त रवीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित परिवार की सीमा तक किया जाए।
9. उक्त धनराशि के देयकों का मुगतान शासनादेश संख्या-3428/स.क./2004-359/स.क./2002 दिनांक 28 फरवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
10. इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय की 'अनुदान संख्या-30' के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-800- अन्य व्यय-07-शिल्पी ग्राम योजना-00' की मानक मद '20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहजता' एवं 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 356(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक 26 सितम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

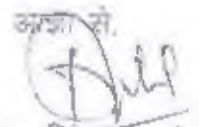

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 4/6 (1)/XVII(1)-01/2007-12(बजट)/2004, तद्विनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ✓ 11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पत्रिका।

अज्ञात से,


(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।